

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 199
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

परिचालन रोजगार कार्यालय

199. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की झारखंड सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) देश में रोजगार कार्यालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान क्रमशः आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य संघ/राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस संबंध में झारखंड सहित सभी राज्यों में लक्ष्य के अनुरूप आधुनिकीकरण की प्रगति हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में लगभग 1008 रोजगार कार्यालय हैं, जिनमें से 43 झारखंड में हैं। देश में रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

सरकार रोजगार संबंधी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे रोजगार मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों आदि संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना के अंतर्गत, सरकार रोजगार कार्यालयों का आदर्श आजीविका केन्द्रों (एमसीसी) में उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दिनांक 22.11.24 की स्थिति के अनुसार, देश में 370 रोजगार कार्यालयों को एमसीसी में उन्नयन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित एमसीसी की राज्य-वार सूची, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

“परिचालन रोजगार कार्यालय” के संबंध में श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 25.11.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (क) से (ड:) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	17
2	अरुणाचल प्रदेश	12
3	असम	52
4	बिहार	47
5	छत्तीसगढ़	26
6	दिल्ली	3
7	गोवा	2
8	गुजरात	46
9	हरियाणा	65
10	हिमाचल प्रदेश	15
11	जम्मू एवं कश्मीर	20
12	झारखंड	43
13	कर्नाटक	40
14	केरल	85
15	मध्य प्रदेश	49
16	महाराष्ट्र	36
17	मणिपुर	11
18	मेघालय	13
19	मिजोरम	3
20	नागालैंड	8
21	ओडिशा	40
22	पंजाब	47
23	राजस्थान	38
24	तमिलनाडु	35
25	तेलंगाना	34
26	त्रिपुरा	6
27	उत्तराखंड	24
28	उत्तर प्रदेश	100
29	पश्चिम बंगाल	77
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	1
31	चंडीगढ़ (यूटी)	2
32	दादरा एवं नगर हवेली (यूटी)	1
33	दमन और दीव (यूटी)	2
34	लक्षद्वीप (यूटी)	1
35	पुडुचेरी (यूटी)	5
36	लद्दाख (यूटी)	2
	योग	1008

“परिचालन रोजगार कार्यालय” के संबंध में श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 25.11.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमसीसी के रूप में उन्नयन किए गए ईईएक्स की संख्या	स्वीकृत कुल राशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक	
				जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)	उपयोग की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	6	255.30	157.53	131.59
2	असम	12	511.77	125.25	117.14
3	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	44.87	0.00 *	0.00 *
4	आंध्र प्रदेश	29	1447.82	293.44	119.82
5	बिहार	20	743.90	128.28	0.00 *
6	छत्तीसगढ़	12	428.97	70.33	0.00 *
7	दिल्ली	1	75.36	0.00 *	0.00 *
8	गोवा	1	13.76	1.21	0.00 *
9	गुजरात	13	382.58	23.00	0.00 *
10	हरियाणा	3	152.89	11.67	0.00 *
11	हिमाचल प्रदेश	2	50.80	6.90	3.94
12	जम्मू और कश्मीर	18	786.84	98.23	91.81
13	लद्दाख	2	101.18	0.00 *	0.00 *
14	झारखंड	20	852.98	184.83	0.00 *
15	कर्नाटक	13	464.82	62.74	0.00 *
16	केरल	13	724.99	0.00 *	0.00 *
17	लक्षद्वीप	1	49.56	3.55	2.30
18	महाराष्ट्र	26	1212.76	442.77	207.66
19	मेघालय	4	172.27	29.04	0.00 *
20	मध्य प्रदेश	11	563.70	58.10	0.00 *
21	मणिपुर	1	84.69	19.14	10.94
22	मिजोरम	4	151.86	66.08	28.58
23	नागालैंड	7	328.23	63.84	63.84
24	ओडिशा	30	1301.99	184.01	164.30
25	पुडुचेरी	4	155.84	25.91	0.00 *
26	पंजाब	12	403.62	130.19	49.05
27	राजस्थान	16	594.42	0.00 *	0.00 *
28	तेलंगाना	12	587.47	112.30	59.37
29	त्रिपुरा	3	150.81	35.33	0.00 *
30	तमिलनाडु	19	1026.79	282.59	127.32
31	उत्तर प्रदेश	35	1560.06	254.96	241.53
32	उत्तराखंड	4	183.95	38.48	15.74
33	पश्चिम बंगाल	15	654.44	132.55	20.79
योग		370	16221.29	3042.25	1455.72

* 0 आंकड़ा यह दर्शाता है कि पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (अर्थात् 2021-22 से 2024-25 तक) के दौरान राशि जारी/उपयोग नहीं की गई है।